हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 57 | देहरादून, बुधवार, 17 अगस्त, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

सीएम को सौंपा गया स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का पहला प्रतिवेदन 3

पंचायत मंत्री सतपाल महाराज ने बताया पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पहले प्रतिवेदन की अहमियत

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। उत्तराखण्ड के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रह्म सिंह वर्मा ने धामी को पहला प्रतिवेदन सौंपा इस दौरान पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुति जनपद हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में अंतरिम संस्तुति है, जो अंतिम प्रतिवेदन के अधीन होगी।पंचायतीराज मंत्री महाराज ने कहा कि आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन में जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 171 (54.13 प्रतिशत) प्रधान पदों के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 69 (22.03 प्रतिशत) पदों की संस्तुति की है।

उन्होने बताया कि जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 3 (54.13 प्रतिशत) प्रमुख पदों के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 1 (16.66 प्रतिशत) पद की संस्तुति की है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया राज्य के अन्य 12 जनपदों में पूर्ण न होने के कारण जनपद हरिद्वार में अध्यक्ष जिला पंचायत पद के आरक्षण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई संस्तुति नहीं की गई है।जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 362 ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये गये हैं। कतिपय ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने के कारण एकल समर्पित आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 281 सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है, जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का समग्र आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत है।उन्होने बताया कि जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 27 क्षेत्र पंचायत सदस्य (वार्ड) के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 27 सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है, जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है।जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 6 जिला पंचायत सदस्य (वार्ड) के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 6 सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है, जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है।इस अवसर पर पंचायतीराज सचिव पंचायतीराज नितेश झा, निदेशक पंचायतीराज बंशीधर तिवारी, अपर सचिव ओंकार सिंह उपस्थित थे।

वित्तमंत्री और स्पीकर ने न्यूज़ वायरस की विशेष पुस्तक धामी विजन 2025 का किया विमोचन

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड की विधान सभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी और वित्तमंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार की सौ दिन की उपलब्धियों और विजन 2025 पर आधारित विशेष पुस्तक धामी विजन 2025 की सराहना करते हुए इसे एक बेहतरीन दस्तावेज़ बताया है। देहरादून में पुस्तक का अनवराड़ करते हुए स्पीकर और संसदीय कार्यमंत्री ने न्यूज़ वायरस हिंदी दैनिक की सराहना करते हुए इस किताब को सरकार के लिए एक उपलब्धि बताई है।

इसके पहले शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण से उनके देहरादून स्थित शासकीय आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष एवं शहरी विकास मंत्री के बीच प्रदेश के विकास एवं समसामयिक विषयों पर चर्चा वार्ता हुई ।इस मुलाकात के दौरान शहरी विकास मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पौधा भेंट किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र को लेकर विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए शहरी विकास मंत्री से विस्तार में वार्ता की । इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने नगर निगम कोटद्वार से संबंधित ट्रेंचिंग ग्राउंड, एसटीपी प्लांट एवं नगर के सौंदर्यकरण सहित कई अन्य विषयों को लेकर बातचीत की। शहरी विकास मंत्री ने भी सभी मुद्दों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को समाधान के लिए आश्वस्त किया ।

पर्वतीय क्षेत्रों में मिले स्थाई सीसीबी की स्वीकृति : डॉ0 धन सिंह रावत

कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में रखी मांग

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य से संबंधित प्रदेश के मुद्दे रखे। उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुये पर्वतीय क्षेत्रों में स्थाई क्रिटीकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण की स्वीकृति देते हुये बजट बढ़ाने की मांग की।

कहा, राज्य को उपलब्ध करायें अतिरिक्त प्रीकॉशन डोज

प्रीकॉशन डोज टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिये स्वास्थ्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वैक्सीन उपलब्ध कराने, कोविड काल में स्वीकृत अवशेष धनराशि को खर्च करने एवं एनएचएम के अंतर्गत प्रथम किस्त जारी करने का अनुरोध किया। जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सकारात्मक रूख अपनाते हुये शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में शिरकत की। बैठक में डॉ0 रावत ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुये पर्वतीय क्षेत्रों में स्थाई क्रिटीकल केयर ब्लॉक के निर्माण की स्वीकृति की मांग की। उन्होंने बताया कि प्री-फेब्रिकेटेड सीसीबी के निर्माण हेतु केन्द्र द्वारा स्वीकृत 9.50 लाख की धनराशि पर्याप्त नहीं है जबकि रूपये 25 लाख की लागत से पर्वतीय जनपदों में स्थाई सीसीबी का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पर्वतीय जनपदों में स्थाई सीसीबी निर्माण हेतु रूपये 25 लाख की मांग की। डॉ0 रावत ने राज्य में प्रीकॉशन टीकाकरण अभियान में और अधिक तेजी लाने के लिये अतिरिक्त वैक्सीन की मांग रखी। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य में अबतक 18 फीसदी लोगों को प्रीकॉशन डोज लग चुके हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बैठक में डॉ0 रावत ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कोविड वैक्सीनेशन के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत बजट को वापस न लिये जाने एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रथम किस्त जारी करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि बजट न मिलने से एनएचएम के कार्मिकों को विगत कई माह से वेतन-भत्ते नहीं मिल पाये हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। आयुष्मान योजना की जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि सूबे में अब तक करीब 49 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं तथा योजना के अंतर्गत 5.50 लाख लोगों का उपचार भी किया जा चुका है। जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुशी जाहिर की और राज्य से जुड़े मुद्दे पर सकारात्मक सहायोग का आश्वासन दिया। बैठक में प्रभारी सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम आर राजेश, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ0 शैलजा भट्ट, निदेशक एनएचएम डॉ0 सरोज नैथानी, वित्त नियंत्रक खजान चन्द्र पाण्डे सहित शहरी विकास विभाग के अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अल्मोड़ा विवि के तीनों परिसरों में शीघ्र करें शिक्षकों की तैनाती : धन सिंह रावत

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के तीनों परिसरों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टॉफ की शीघ्र तैनाती के निर्देश उच्चाधिकारियों को दे दिये गये हैं। विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में इसी सत्र से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने एवं विधिवत कक्षाएं संचालित करने को कहा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की शीघ्र तैनाती करने के निर्देश विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिये। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 एन0एस0 भण्डारी ने बताया कि पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर परिसरों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की तैनाती के लिये सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई है। जिसके तहत शैक्षणिक पदों के लिये कमेटी द्वारा साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है। इसी प्रकार शिक्षणेत्तर पदों के लिये कार्मिकों से विकल्प मांग कर सूची तैयार कर ली गई है। जिस पर अग्रिम कार्यवाही कर दो सप्ताह के भीतर कार्मिकों की सूची जारी कर दी जायेगी। कुलपति ने कहा उनका प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में पूर्व की भांति सभी संकायों में अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाय। बैठक में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, कुलपति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा प्रो0 एन0एस0 भण्डारी, कुलपति कुमाऊं विवि प्रो0 एन0के0 जोशी, निदेशक उच्च शिक्षा प्रो0 एस0के0 शर्मा, सलाहकार रूसा प्रो0 एम0एस0एम0 रावत, प्रो0 के0डी0 पुरोहित, अपर सचिव एम0एम0 सेमवाल, संयुक्त निदेशक एवं नोडल रूसा डॉ0 ए0एस0 उनियाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी में खुलेंगे दो अन्य विषयजंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषय को मिलेगी स्वीकृति उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने शिक्षकों के तैनाती, भवन निर्माण, प्रवेश प्रक्रिया की प्रगति, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सहित तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी में शीघ्र जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्वीकृति प्रदान करने एवं शिक्षकों की तैनाती करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन महाविद्यालयों में निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाय तथा जिन महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त है वहां पर शिक्षकों शीघ्र तैनाती की जाय। महाविद्यालयों में सफाई व्यवस्था के लिये आउट सोर्स एजेंसी अथवा आउट सोर्स कार्मिकों की तैनाती के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये। बैठक में प्राचार्य थलीसैण महाविद्यालय प्रो0 रेनु रानी बंसल, प्राचार्य मजरा महादेव प्रो0 के0सी0 दुदपुडी, प्रभारी प्राचार्य खिर्सू महाविद्यालय प्रो0 डी0एस0 नेगी, डॉ0 कुलदीप सिंह रावत, डॉ0 आलोक कंडारी, डॉ0 रजनी बाला, डॉ0 विकास राणा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास खबर, सीनियर सिटीजन कार्ड बनाकर पाएं हजारों का लाभ

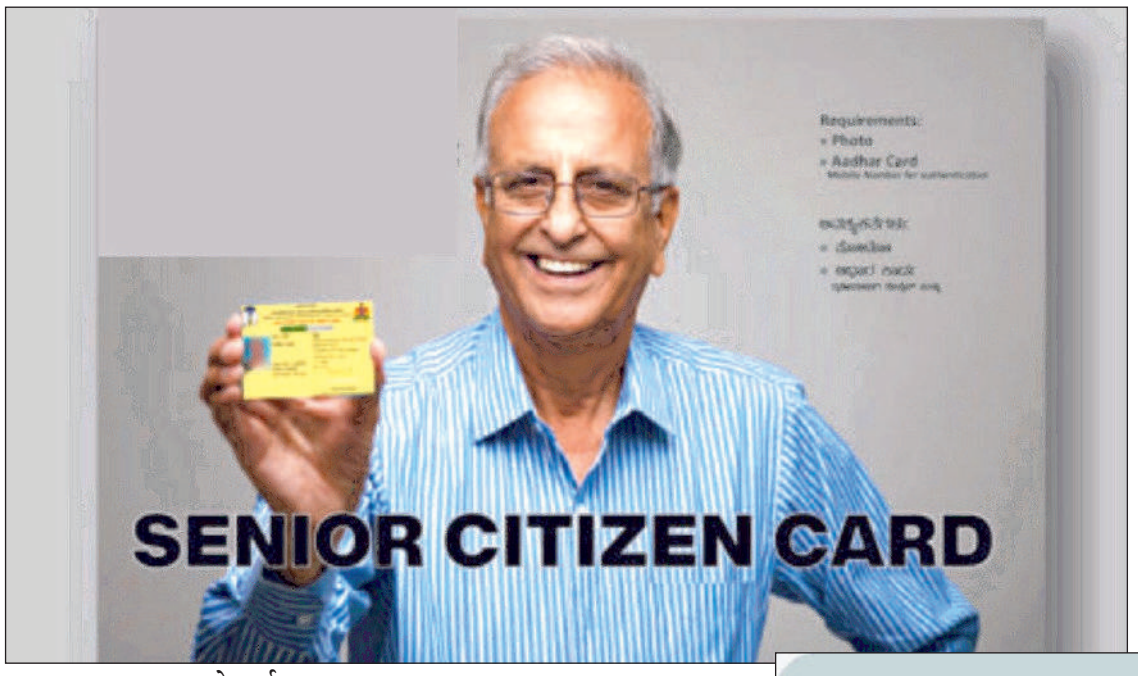

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उनके लिए यह खबर काफी अहम हो सकती है। आए दिन की बदहाली को देखते हुए सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ढेर सारी योजनाएं लेकर आती है, इस खबर में हम आपको सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में बताएंगे, जिससे आपको हजारों का फायदा हो सकता है।

बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों और उनकी रोजमर्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार वरिष्ठ नागरिकों का कार्ड बनाती है। यह कार्ड 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है, जिसे वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड भी कहा जाता है। यह कार्ड भी एक तरह का पहचान पत्र है जो कार्डधारक का विवरण बताता है। इस कार्ड की मदद से वरिष्ठ नागरिकों को कई खास सुविधाएं दी जाती हैं। इस कार्ड की मदद से सरकारी और निजी योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। इस कार्ड में वरिष्ठ नागरिकों के रक्त समूह, आपातकालीन संपर्क नंबर, एलर्जी और अन्य दवा विवरण दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड कैसे बनता है।

वरिष्ठ नागरिक कार्ड राज्य सरकारें अपने स्तर पर बनाती हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी जमा करने होते हैं ताकि आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

1-एज प्रूफ के लिए दस्तावेज :इसके लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दिया जा सकता है।

2-निवास प्रमाण पत्र के कागजात :इसमें आवेदक के नाम से वैध दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, बिजली या फोन बिल दिया जा सकता है

3- चिकित्सा सूचना दस्तावेजइसमें ब्लड रिपोर्ट, दवा और एलर्जी की रिपोर्ट देनी होती है।

4- 3 स्टाम्प साइज फोटो भी संलग्न करना होगा

क्या है सीनियर सिटीजन कार्ड के लाभ

पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में किराए में रियायत दी जाती थी, लेकिन अब यह बंद है। हालांकि, अब भी एक अलग टिकट काउंटर उपलब्ध कराया गया है। फ्लाइट टिकट में छूट दी जाती है। अन्य की तुलना में आयकर कम है, साथ ही कुछ मामलों में रिटर्न दाखिल करने से छूट भी है। FD पर आम जनता से ज्यादा ब्याज मिलता है। डाकघर निवेश योजना आम लोगों की तुलना में अधिक लाभ और सुविधाएं प्रदान करती है।

सरकारी अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में रियायती दरों पर मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल के लिए आवेदन करने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज और मासिक रेंटल चार्ज में छूट भी मिलती है।

कैसे करते हैं अप्लाई

सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड बनाने के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसका फॉर्म केवल राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है जहां इसे ऑनलाइन भरा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए या वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में अन्य जानकारी के लिए, टोल-फ्री नंबर 1291 या 100 पर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

क्या आपको पता है 20 मई, 1873, को नीली जींस का 'जन्मदिन' होता है

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

लेवी स्ट्रॉस कंपनी के अनुसार, यह वह दिन था जब लेवी स्ट्रॉस और जैकब डेविस, मजबूत नीली जींस के पीछे के नवप्रवर्तन कर्ता, जिन्हें हम सभी प्यार करते हैं, को पुरुषों की डेनिम वर्क पैंट में धातु के रिवेट्स जोड़ने की प्रक्रिया पर पेटेंट मिला। 1960 तक पैंट को कमर चौग़ा कहा जाता था, जब बेबी बूमर्स ने उन्हें जींस कहना शुरू किया। यही कारण है कि नीला सबसे लोकप्रिय डेनिम रंग है।

1853 में, कैलिफोर्निया सोने की भीड़ पूरे जोरों पर थी, और रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति कम थी। लेवी स्ट्रॉस, एक 24 वर्षीय जर्मन आप्रवासी, अपने भाई के न्यू यॉर्क ड्राई गुड्स व्यवसाय की एक शाखा खोलने के इरादे से सूखे माल की एक छोटी आपूर्ति के साथ न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुआ। उनके आगमन के कुछ समय बाद, एक भविष्यवक्ता ने जानना चाहा कि मिस्टर लेवी स्ट्रॉस क्या बेच रहे हैं। जब स्ट्रॉस ने उसे बताया कि उसके पास टेंट और वैगन कवर के लिए उपयोग करने के लिए एक मोटा कैनवास है, तो प्रॉस्पेक्टर ने कहा, ₹आपको पैंट लाना चाहिए था!₹ यह कहते हुए कि उन्हें पैंट की एक जोड़ी इतनी मजबूत नहीं मिली कि वह टिक सके।

लेवी स्ट्रॉस ने कैनवास को कमर के चौग़ा में बनाया था। खनिकों ने पैंट पसंद किया लेकिन शिकायत की कि वे झगड़ते थे। लेवी स्ट्रॉस ने फ्रांस से ₹सर्ज डी निम्स₹ नामक एक सूती कपड़े को प्रतिस्थापित किया। कपड़े को बाद में डेनिम के रूप में जाना जाने लगा और पैंट को नीली जींस का उपनाम दिया गया।

आईआरडीई कर्मचारी संघ को मान्यता मिलने से दून में जश्न

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आईआरडीई कर्मचारी संघ देहरादून द्वारा चार वर्ष पूर्व भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता मांगी गई थी। रक्षा मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2022 को आईआरडीई कर्मचारी संघ को मान्यता प्राप्त हुई। रक्षा मंत्रालय का मान्यता पत्र आज प्राप्त हुआ। पत्र प्राप्ति की खबर से आईआरडीई कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल आ गया। इस खुशी के अवसर पर कर्मचारियों में आईआरडीई के मैन गेट से स्टेट तक रैली निकाल पटके जलाए और मिठाई बाटी। पूरी रैली में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। इस रैली में कर्मचारी संघ के अतिरिक्त भारतीय मजदूर संघ (BMS) के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली में आईआरडीई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, सम्मानित सदस्यो के अतरिक्त भारतीय मजदूर संघ जिला देहरादून के उपाध्यक्ष उज्जवल त्यागी, जिला सहमंत्री लोकेश देवराडी, पूर्व जिलामंत्री पंकज शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष अवनीश कांत, आयुध निर्माणी के महामंत्री देवाशीष शर्मा, सहायक मंत्री प्रवीण कांबोज, संगठनमंत्री दीपक शर्मा व बसंत गुप्ता, कोषाध्यक्ष अनुज कुमार एमईएस से महामंत्री केसर सिंह और राजकुमार, ओएलएफ से तोमर, ओमप्रकाश, अजीत सिंह, अरुण कुमार, मोहित मुकेश, पवन, सुनील, विपिन, आशुतोष, कुलवंत, हेमंत आदि लोग सम्मलित हुए।भारतीय मजदूर संघ एवम अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने आईआरडीई कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी।

डैटोल स्कूल हाईजीन एजुकेशन प्रोग्राम लाएगा परिवर्तन : मुख्यमंत्री

सलीम सैफ़ी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डैटोल स्कूल हाईजीन एजुकेशन प्रोग्राम उत्तराखण्ड का शुभारंभ किया। डैटोल स्कूल हाईजीन एजुकेशन प्रोग्राम उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों के 13 हजार प्राथमिक स्कूलों में चलाया जायेगा। इसके लिए शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी एवं डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स एवं पार्टनरशिप, एसओए, रेकिट रवि भटनागर के मध्य एमओयू भी हस्ताक्षरित किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डैटोल स्कूल हाईजीन एजुकेशन प्रोग्राम से बच्चों में स्वच्छता के प्रति एवं दैनिक व्यवहार में परिवर्तन आयेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों में व्यक्तिगत, स्कूलों, घरों एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जन्म से 06 वर्ष की आयु तक बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। जीवन के शुरूआती चरण में बच्चों को जो अनुशासन मिलता है, उसी का अनुसरण कर बच्चे आगे बढ़ते हैं। आने वाले 25 साल देश का अमृतकाल के होंगे, आज के ये बच्चे 25 साल बाद देश के कर्णधार होंगे। इनको सही दिशा देना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिये राज्य में 4457 को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाल वाटिकायें प्रारम्भ हो चुकी हैं। 'प्रवेशोत्सव', 'आरोही', 'कौशलम', 'आनन्दम', 'विद्या सेतु' जैसे नए कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय स्टूडियो तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति व इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित कराने के उद्देश्य से वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित व भगवत गीता से प्रबन्धन परिचय जैसे विषयों को सह-पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप पॉलिसी लागू की गयी है।

इस अवसर पर सचिव शिक्षा रविनाथ रमन, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स एवं पार्टनरशिप, एसओए, रेकिट रवि भटनागर, एक्सीक्यूटिव डायरेक्टर प्लान इण्डिया मोहम्मद आशिफ उपस्थित थे।

सीएम को सौंपा गया स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का पहला प्रतिवेदन

पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज और सीएम धामी रहे मौजूद

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रह्म सिंह वर्मा ने आयोग का प्रथम प्रतिवेदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुति जनपद हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में अंतरिम संस्तुति है, जो अंतिम प्रतिवेदन के अधीन होगी।

आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन में जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 171 (54.13 प्रतिशत) प्रधान पदों के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 69 (22.03 प्रतिशत) पदों की संस्तुति की है। जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 3 (54.13 प्रतिशत) प्रमुख पदों के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 1 (16.66 प्रतिशत) पद की संस्तुति की है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया राज्य के अन्य 12 जनपदों में पूर्ण न होने के कारण जनपद हरिद्वार में अध्यक्ष जिला पंचायत पद के आरक्षण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई संस्तुति नहीं की गई है।

जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 362 ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये गये हैं। कतिपय ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने के कारण एकल समर्पित आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 281 सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है, जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का समग्र आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत है।

जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 27 क्षेत्र पंचायत सदस्य (वार्ड) के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 27 सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है, जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है। जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 6 जिला पंचायत सदस्य (वार्ड) के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 6 सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है, जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज, सचिव पंचायती राज नितेश झा, निदेशक पंचायती राज बंशीधर तिवारी, अपर सचिव ओंकार सिंह उपस्थित थे।

उत्तराखंड के इस जिले में है शिक्षकों की कमी....

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देश का भविष्य आने वाली युवा पीढ़ी पर टिका है, और इसलिए अगर उनकी शिक्षा ठीक से नहीं होगी तो आने वाली युवा पीढ़ी कैसे मजबूत बनेगी। शिक्षा से ही कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिन्हें जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी है तो शिक्षण कार्यों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कोट प्रखंड के शासकीय इंटर कॉलेज डोंडाल का भी हाल कुछ ऐसा ही है। जहां शिक्षकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने से अभिभावक काफी परेशान हैं।

शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। विद्यालय के परीक्षा परिणाम लगातार प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीण परेशान हैं। स्कूल में रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे महत्वपूर्ण पद खाली चल रहे हैं। वहीं एलटी में जहां गणित का पद खाली है, वहीं अंग्रेजी के शिक्षक भी 2 साल से अटैचमेंट में चल रहे हैं। जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अन्यत्र संलग्न शिक्षकों को स्कूल भेजने की मांग उठाई है।

स्कूल के प्रभारी अवतार सिंह गुसाईं ने माना है कि शिक्षकों की कमी के कारण परीक्षा परिणाम में गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के न होने से बच्चों को भी परेशानी हो रही है। उधर, गढ़वाल मंडल के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि गढ़वाल मंडल के जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। जल्द ही उनमें शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही बताया कि 2 साल से अटैचमेंट में चल रहे शिक्षक को शासन स्तर पर अटैच किया गया है। वह स्वयं न तो आसक्ति के पक्ष में रहता है और न ही किसी शिक्षक से आसक्त होता है।

आयकर छापेमारी में जब्त किए गए धन और संपत्ति का करते क्या हैं? जाने इस खबर में

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हाल ही में आपने सोशल मीडिया, टेलीविजन पर देखा और सुना होगा कि इस शख्स के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और छापेमारी के बाद वह सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए कई तस्वीरें शेयर करते है जो वायरल हो रही होती हैं। जिसमें नजर आ रहा है कि आयकर छापेमारी में काफी पैसा, सोना वगैरह जब्त किया गया है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब इनकम टैक्स के अधिकारी रेड मारते हैं तो क्या होता है, इनकम टैक्स रेड में ऑफिसर्स दबिश देते हैं और फर्जी संपत्ति की जांच करते हैं।

लेकिन, आज हम आपको बताते हैं कि जब्त करने के क्या नियम हैं, और जब्त किए सामान के साथ क्या किया जाता है?

आपको बता दे की छापेमारी करने वाले व्यक्ति से सामान जब्त करने के भी कई नियम हैं। कंप्यूटर आदि की जांच में वे सिस्टम की हार्ड डिस्क अपने साथ ले जाते हैं और नकदी, जेवर जब्त कर लेते हैं। फिर जो सामान जब्त किया जाता है, उसकी जानकारी अगले पक्ष को भी दी जाती है और

फिर उनका सत्यापन किया जाता है। तलाशी अभियान के बाद बयान भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर छापा मारा जाता है तो बिक्री के लिए रखा माल जब्त नहीं किया जाता है।

अब बात करते है जब्त की गई संपत्ति का किया लय जाता है , सबसे पहले तो आयकर विभाग उस पैसे को बैंक में जमा करता है। इनमें आयुक्त से जुड़े खाते भी शामिल हैं। इसके बाद पूरी संपत्ति आय आदि की जांच की जाती है और उसके बाद कर की गणना की जाती है, जिसमें जुर्माना आदि भी शामिल होता है। फिर कर की मांग की गणना की जाती है और न्यायाधिकरण में फिर से सेट की जाती है और शेष भुगतान वापस कर दिया जाता है।

अगर मेरी फिल्में नहीं चलती है, तो में कनाडा जाके कोई भी काम करूगा : अक्षय कुमार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अभिनेता अक्षय कुमार, जिन्होंने इस साल रक्षा बंधन, सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे के साथ कई फ्लॉप फिल्में की हैं, हाल ही में एक साक्षात्कार में उनकी नागरिकता के बारे में पूछा गया था। कनाडा की नागरिकता रखने के लिए अक्षय को अक्सर इंटरनेट पर ट्रोल किया जाता है, और यह मुद्दा आमतौर पर तब उठाया जाता है जब अक्षय राष्ट्रीय कारणों को बढ़ावा देते हैं।

अक्षय ने कहा कि वह ₹एक भारतीय हैं, भारत से हैं, और हमेशा रहेंगे।₹ उन्होंने याद किया कि उन्हें कनाडा की नागरिकता ऐसे समय में मिली थी जब उनकी फिल्मों ने काम करना बंद कर दिया था और वे कनाडा जाने के बारे में सोच रहे थे। "कुछ साल पहले, मेरी फिल्में काम नहीं कर रही थीं। लगभग 14-15 फिल्मों ने काम नहीं किया था इसलिए मैंने सोचा कि मुझे शायद कहीं और जाकर वहां काम करना चाहिए।

अक्षय ने कहा कि उनका एक दोस्त कनाडा में रहता था और उसने सुझाव दिया कि अगर अक्षय को भारत में सफलता नहीं मिल रही है तो उसे भी वहीं चले जाना

चाहिए। "बहुत सारे लोग काम के लिए वहां जाते हैं, लेकिन वे अभी भी भारतीय हैं। तो मैंने भी सोचा कि अगर नियति यहां मेरा साथ नहीं दे रही है तो मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मैं वहां गया, इसके (नागरिकता) के लिए आवेदन किया और मिल गया। अक्षय ने कहा कि इसके तुरंत बाद, उन्हें फिर से पेशेवर सफलता का अनुभव होने लगा, और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें वापस रहना चाहिए। ₹फिर मैंने सोचा कि मैं अपने देश में रहूंगा, फिर कभी जाने के बारे में नहीं सोचा,₹

ट्रेन यात्रा में सामान खोने की टेंशन से मुक्त कर देगी ये खबर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक राकेश शर्मा लगातार कई सालों से आम लोगों को अपना सामान खोने की परेशानी से मुक्ति दिलाते रहे हैं। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। राकेश शर्मा ने बताया कि सरकारी काम के पहाड़ खड़ा हो जाता है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए मैंने यह पहल की है। स्टेशन प्रबंधक राकेश शर्मा ने बताया कि जब से उन्होंने यह अभियान शुरू किया है तब से अब तक 506 राहगीरों तक उनका माल सुरक्षित पहुंचा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह वर्ष 1998 से रेलवे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्ष 2016 से

अलावा यह उनका अभियान है, जिससे आम लोगों का खोया हुआ सामान उन तक पहुंचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की एक कीमत होती है, लेकिन उस वस्तु से जुड़ी भावनाएं अनमोल होती हैं। जब भी कोई अपना सामान खोता है तो उसके सामने मुसीबतों का लोगों तक सामान पहुंचाने का अभियान शुरू किया. , कुली, खानपान कर्मचारी। ऐसे में उनकी कोशिश होती है कि बर्थ के नीचे या नीचे वाली बर्थ के पीएनआर नंबर के जरिए लोगों तक पहुंचे. जन्म संख्या प्राप्त करने के बाद, मैं उनके फ़ोन नंबर, या एजेंट के फ़ोन नंबर के माध्यम से उनके फ़ोन नंबर तक पहुँचता हूँ। फिर मैं उन्हें सामान दिलाने में मदद करता हूं।

पासपोर्ट से लेकर वीजा तक हर चीज को लेकर राकेश शर्मा ने कहा कि कई बार लोग अपना बैग भूल जाते हैं, जिसमें पासपोर्ट से लेकर जरूरी सामान होता है। कोशिश की कि उनके बैग जल्द से जल्द ऐसे लोगों तक पहुंचाए जाएं. उन्होंने कहा कि हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत है. जिसमें सफाईकर्मी से लेकर कर्मचारी तक शामिल हैं।राकेश शर्मा ने कहा कि कभी-कभी सरकारी दस्तावेज सामान में होते हैं। कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड। ऐसे में वह इन दस्तावेजों के जरिए भी यात्रियों तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसमें मोबाइल नंबर काफी मददगार साबित होता है। राकेश शर्मा ने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं सीधे यात्री तक सामान पहुंचा देता हूं। इसके लिए पहले मैं इसे वेरीफाई भी करता हूं। जब मैं संतुष्ट हो जाता हूं कि ऐसी जानकारी संबंधित यात्री के सामान से संबंधित है, तो मैं उस यात्री को सामान सौंप देता हूं।

एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर के टॉप निर्देश जारी - अब पालन की तयारी

फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों तथा चौकी प्रभारियो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी के दौरान एसएसपी ने कई अहम निर्देश दिए हैं -

1- आमजन के माध्यम से थाना/ चौकियों में अभियोग पंजीकृत करने में देरी किये जाने सम्बन्धित शिकायते प्राप्त हो रही है। जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को प्राप्त शिकायतों पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करने तथा गुण –दोष व उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर उनका विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

2- पूर्व में दिये गये आदेशो के बावजूद भी थाना प्रभारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर स्वयं मौके पर जाकर जानकारी नही की जा रही है। जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये महोदय द्वारा प्राप्त शिकायतों पर पूर्व में दिये गये निर्देशो के अनुरुप स्वय थाना प्रभारी /चौकी प्रभारी द्वारा 30 मिनट के अन्दर मौके पर जाकर घटनाक्रम की जानकारी करने तथा ऐसी परिस्थितियों में जिनमें स्वयं वह मौके पर न जा सके उनमे कम से कम 02 सिपाहियो को मौके पर भेजने के निर्देश दिये गये तथा स्पष्ट किया की इसमें कोताही बरतने वाले थाना /चौकी प्रभारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।3- थाना/ चौकियों में बिचौलियों, भू- माफियाओं , आपराधिक पृष्ट भूमि के लोगो को ना आने दिया जाये, किसी भी शिकायत पर सीधे शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर उसकी समस्या का विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। 4- SC/ST act तथा बलात्कार व पोक्सो के मामलो में निर्धारित समयावधि के भीतर विवेचना का निस्तारण करना सुनिश्चित करें, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाये। बिना किसी कारण के अनावश्यक रूप से विवेचनाओ को लम्बित रखने वाले विवेचको के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

5- वर्तमान में मालो के निस्तारण हेतु जनपद में अभियान चल रहा है। अतः सभी थाना प्रभारी इसे गंभीरता से लेते हुये उक्त अभियान के तहत एन0डी0पी0एस0 व अन्य मुकदमों से सम्बन्धित मालो तथा थाने पर खड़े लावारिस वाहनो का अधिक से अधिक निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

6- यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे परन्तु थाना /चौकी प्रभारियों द्वारा यातायात व्यवस्था में सुधार की दिशा न ही अपेक्षानुरुप कार्य किया जा रहा है और ना ही वह अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। सभी थाना/ चौकी प्रभारी इस बात को सुनिश्चित कर ले की यातायात व्यवस्था में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

7- देखने में आ रहा है कि थाना प्रभारियों द्वारा दिन व रात्रि के समय थाने से जाने वाली ड्यूटियों को ब्रीफ नहीं किया जा रहा है और ना ही उनके द्वारा अधिनस्त नियुक्त कर्मियों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। सभी थाना प्रभारी अपने अधीनस्थ नियुक्त चौकी प्रभारियों के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों के कार्यों की भी नियमित रूप से समीक्षा करें तथा जिन पुलिस कर्मियों द्वारा अपेक्षानुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट तत्काल उच्चाधिकारियों को भेजें।

8- प्रातः काल स्कूल खुलने का समय यातायात व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी सीपीयू व ट्रैफिक कर्मियों की होगी, परन्तु उसके उपरांत पीक आवर (ऑफिस खुलने का समय, स्कूलों की छुट्टी के समय, शाम ऑफिस छूटने के समय) यातायात पुलिस के साथ-साथ सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी तथा चौकी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र के व्यस्ततम मार्गों व यातायात के दबाव वाले क्षेत्रों मे स्वयं मौजूद रहते हुए यातायात का सुचारू संचालन करना सुनिश्चित करेंगे।

9- सभी थाना/चौकी प्रभारी तथा यातायात पुलिसकर्मी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तिराहे/ चौराहे पर लेफ्ट टर्न किसी भी दशा में बाधित ना हो क्योंकि अक्सर लेफ्ट टर्न के बाधित होने से चौराहों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है, इसकी मुख्य वजह विक्रम, ऑटो, सिटी बस चालकों व अन्य वाहन चालकों द्वारा मुख्य मार्गो पर इधर-उधर अपने वाहनों को खड़ा करना है। अतः सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में यातायात को बाधित करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध आवश्यक चलानी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

10- जिन- जिन स्थानों पर महोदय द्वारा पूर्व में यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर यातायात संचालन हेतु पुलिस कर्मियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे, उन सभी स्थानों पर पुलिसकर्मियों को नियुक्त करते हुए बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग व शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर अभी भी रेहड़ी/ ठेली वालों द्वारा अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों पर घूमते हुए यातायात को बाधित किया जा रहा है, सभी थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

11- वर्तमान में बरसात के मौसम के दृष्टिगत शहर के विभिन्न स्थानों पर मुख्य मार्गों पर गड्ढे होने के कारण उक्त मार्गो पर यातायात अनावश्यक रूप से धीमा/बाधित हो रहा है। सभी थाना प्रभारी अपने- अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए वहाँ आवश्यक पुलिस बल को नियुक्त करते हुए पीक आवर्स के दौरान स्वयं भी वहाँ मौजूद रहना सुनिश्चित करें।

12- सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग तथा खनन कार्यों से जुड़े बाहरी/ स्थानीय व्यक्तियों की सूची तैयार करते हुए इस बात की जानकारी कर ले कि कितने लोगों के पास खनन अथवा भंडारण की अनुमति है तथा इनमें से कितने व्यक्ति अवैध रूप से खनन तथा प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य में संलिप्त है, ऐसे व्यक्तियों का प्रोफाइल तैयार करते हुए उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी कर ली जाए तथा उक्त व्यक्तियों उनके सहयोगियों के विरुद्ध गुंडा व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।

13- थानाध्यक्ष सहसपुर/ सेलाकुई/ प्रेम नगर तथा प्रभारी निरीक्षक विकासनगर को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्रों में 3 दिन का विशेष अभियान चलाते हुए थाना क्षेत्र में निवासरत बाहरी व्यक्तियों, फैक्ट्रीयो में काम करने वाले मजदूरों के सत्यापन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा जिन मकान मालिकों द्वारा अपने किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराया गया उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए।

14- किसी भी थाना क्षेत्र में होटल, ढाबों, रेस्ट्रॉन्ट आदि में शराब का सेवन नहीं किया जाएगा, यदि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी थाना क्षेत्र में इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी की जवाबदेही तय करते हुए उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, इसके अतिरिक्त सभी अधिकारी/ कर्मचारी वर्तमान में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ड्यूटी के दौरान आवश्यक सावधानी बरतें तथा स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल अपना इलाज कराएं।

मंत्री सौरभ बहुगुणा की संवेदनशीलता से बची दो घायलों की जान

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड के युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा यूँ तो अपनी बेहतरीन कार्यशैली के लिए लोकप्रिय हैं लेकिन उनकी संवेदनशीलता भी दिल को छू लेने वाली है। इस एहसास को लोगों ने उस वक़्त महसूस किया जब श्रीनगर एनएच पर बागवान के पास एक प्राइवेट बस और बाइक की टक्कर से बाइक पर सवार दो व्यक्ति आशीष केसरी और अनीस कुमार गंभीर रूप से घायल लोगों के पास खुद मंत्री सौरभ अपने काफिले से उत्तर कर पहुंचे और दर्द में तड़प रहे घायलों की तरफ मदद के लिए हाँथ बढ़ाया। आपको बता दें कि दुर्घटना के कुछ देर बाद ही रुद्रप्रयाग दौरे से देहरादून आते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। संवेदनशीलता का ये कोई पहला उदाहरण नहीं है इसके पहले भी जनता के लिए समर्पण भाव दिखाने वाले मन्त्री सौरभ बहुगुणा ने फ़ेसबुक पोस्ट का संज्ञान लेते हुए बागेश्वर के दुग-नाकुरि तहसील के छातिखेत पल्सो निवासी पंकज के इलाज की व्यवस्था की थी। पंकज के दिल में छेद था।जानकारी के मुताबिक यूपी के सोनभद्र निवासी दोनों घायलों का उपचार बेस अस्पताल श्रीकोट में चल रहा है। बस ऋषिकेश से गुप्तकाशी जा रही थी तभी अचानक बस के सामने तेज रफ़्तार बाइक सवार दो युवक आ गए और उनकी बस से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे वे घायल हो गए।दोनों की हालत अभी खतरे से

बाहर बताई जा रही है।इस नज़ारे को देखने वाले सैकड़ों ग्रामीणों और राहगीरों ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की जमकर सराहना करते हुए उन्हें इसी तरह ज़रूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर काम करने की दुआएं दी है।

भूस्खलन से बढ़ रहा है केदारनाथ, चारधाम यात्रा पर असर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड में बारिश धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन भूस्खलन का दौर अभी भी जारी है। हाल ही में केदारनाथ हाईवे पर बिना बारिश के पहाड़ी दरक रही है। जिससे चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। लग रहा है। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग तहसील के पास पहाड़ से चट्टान टूटी हुए दिखाए दी है।

आपको बता दें कि बारिश में कच्ची हो गई पहाड़ियां इन दिनों बिना बारिश के ही टूट रही हैं। खासतौर पर केदारनाथ हाईवे पर स्लाइडिंग जोन पर अक्सर भूस्खलन होता रहता है। इससे केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भूस्खलन स्थलों पर हाइवे पर यात्रा कर रहे स्थानीय लोग और तीर्थयात्री भी लापरवाही दिखा रहे हैं।

लोग भूस्खलन वाले स्थानों पर पहाड़ी से टूटी चट्टानों के बीच आवाजाही कर रहे हैं। ऐसी चट्टानों के बीच से आवाजाही खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा ही कुछ रुद्रप्रयाग

त्रिस्तरीय एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की मासिक समीक्षा करेंगे डीजीपी

स्टेट एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के थाना क्षेत्र में जाकर ड्रग्स पकड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी पर होगी कार्यवाही

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री धामी द्वारा वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को नशामुक्त करने हेतु Drugs Free Devbhoomi by 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए त्रिस्तरीय एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का राज्य, जनपद और थाना स्तर पर गठन किया गया है। इसी परिपेक्ष जनपद देहरादून के वरिष्ठ अधिकारियों, थानाध्यक्षों, निरीक्षक व उप निरीक्षकों को ड्रग्स के प्रति संवेदनशील करने, ड्रग्स के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से उत्तराखण्ड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अभियोजन के अधिकारियों द्वारा ड्रग्स के विरूद्ध कार्यवाही को और अधिक प्रभावी करने, enforcement और awareness की कार्यवाही, विधिक और कानूनी रूप से मजबूत विवेचना करने के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बताया गया।*

कार्याशाला को सम्बोधित करते हुए अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड ने कहा कि ड्रग्स हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। किसी परिवार का बच्चा यदि ड्रग्स के जाल में फंस जाता है तो उस परिवार की जीवन भर की कमाई, इज्जत सब बरबाद हो जाती है इससे अच्छे-अच्छे परिवार भी बरबार हो जाते हैं। ड्रग्स को समूल नाश करना हमारी जिम्मेदारी है। ड्रग्स पूरी दुनियां में टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत है इस नाते हमारी ड्यूटी और अधिक बढ़ जाती है। ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनायें।सामाजिक, सवैंधानिक जिम्मदारी के साथ-साथ थानाध्यक्ष होने के नाते आपकी काफी जिम्मेदारी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं थाना स्तर पर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यदि राज्य स्तर की टास्क फोर्स किसी थाने क्षेत्र पर जाकर ड्रग्स पकडती है, तो सम्बन्धित थाना प्रभारी की भी जवाबदेही तय की जाएगी। Enforcement, Awareness एवं Rehab तीनों को साथ लेकर चलें। पूरी युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा में लगाना है। आप सभी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी के सपने ड्रग्स फ्री देवभूमि को साकार करें। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा अपनी उर्जा को सकारात्मक क्रिया-कलापों खेल, पढाई, कल्चरल एक्टीविटी आदि में लगाएं और ड्रग्स से दूर रहें।

कार्यशाला में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड- वी मुरूगेशन ने अभियुक्तों के विरूद्ध मा0 न्यायालयों में प्रभावी पैरवी, साक्ष्य प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विवेचनाओं में गुणवत्ता लाये जाने के सम्बन्ध में बताया गया। श्री गिरीश चन्द्र पंचौली- संयुक्त निदेशक, विधि, देहरादून द्वारा एवं मनोज कुमार शर्मा- एडीजीसी, देहरादून द्वारा मा0 न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित मामलों में विचारण के दौरान पाई जाने वाली कमियों तथा वर्तमान तक आने वाली कमियों की पूर्ति विवेचना के दौरान करने हेतु भी विस्तारपूर्वक समझाया गया।

नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए पूरे प्रदेश में वर्ष 2019 में 1558 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करके 11 करोड़ से अधिक का मादक पदार्थ बरामद किया गया। वर्ष 2020 में 1490 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करके लगभग 13 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद किया गया। 2021 में 2165 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करके 26 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद किया गया। इसी

प्रकार वर्ष 2022 के प्रथम 06 माह में 794 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करके 12 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद किया गया।कार्यशाला में पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र- करन सिंह नगन्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून- दलीप सिंह कुंवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ अजय सिंह सहित जनपद के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय

गौरवपूर्ण आर्थिक यात्रा...

कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश जब आज से 75 वर्षपहले स्वतंत्रहुआ, तो वह औपनिवेशिक शासन के दमन व शोषण से जर्जर और निर्धन हो चुका था. उस समय भारत का सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) मात्र 2.7 लाख करोड़ रुपये था. अमृत महोत्सव के इस वर्षमें यह आंकड़ा 236 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. आज हम न केवल शीर्षस्थ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हैं, बल्कि तमाम बाधाओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि की गति सर्वाधिक है. वर्ष1950 में हमारी प्रति व्यक्ति आय 265 रुपये थी, जो आज 1.30 लाख रुपये के आसपास है. यह बढ़ोतरी 500 गुना से भी अधिक है. विदेशी मुद्रा भंडार 1.82 अरब डॉलर से बढ़ कर 573 अरब डॉलर हो चुका है. सिंचाई सुविधाओं के अभाव, सूखे व बाढ़ जैसी समस्याओं के कारण हमें कभी खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है, लेकिन दशकों के प्रयास से भारत इस मामले में आत्मनिर्भर होने के साथ दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों की सूची में भी है. आर्थिक प्रगति के स्तर का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हमारी जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 53 प्रतिशत हो चुकी है. विभिन्न कारणों से स्वतंत्रता के पहले डेढ़ दशकों में हमारा निर्यात बहुत कम भी था और उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी. धीरे-धीरे होते औद्योगिक विकास और उद्यमिता के विस्तार ने विकास यात्रा को एक बड़ा आधार दिया और तीन दशक पहले उदारीकरण के लागू होने के बाद से हमारा निर्यात निरंतर बढ़ता जा रहा है. बीते वित्त वर्षमें कुल निर्यात लगभग सवा चार सौ अरब डॉलर रहा था. दुनिया के अग्रणी देश- अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदि- हमारे उल्लेखनीय व्यापारिक साझेदार हैं. आज हम दवाओं के सबसे बड़े निर्माता हैं, जिस कारण भारत को 'दुनिया का दवाखाना' भी कहा जाता है. विभिन्न रोगों के टीकों की 50 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति भारत से ही होती है. सीमेंट, इस्पात और कोयले के उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे पायदान पर हैं तथा बिजली उत्पादन में तीसरे स्थान पर आ चुके हैं. हमारी शानदार आर्थिक प्रगति का एक संकेतक यह भी है कि 1951 में जहां तीन लाख वाहनों का पंजीकरण हुआ था, वहीं यह संख्या 2019 में 2.90 करोड़ हो गयी. बीते दस वर्षों में वाहन पंजीकरण में लगभग 9.91 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है. गरीबी उन्मूलन, आवास उपलब्धता, रोजगार, कौशलयुक्त शिक्षा, तकनीक, वित्तीय प्रबंधन आदि मामलों में हमारा विकास विश्व के समक्ष एक आदर्श है. साढ़े सात दशकों की इस प्रगति पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए तथा नीति निर्धारकों, श्रमिकों, किसानों, कारोबारियों, प्रबंधकों, उद्यमियों, तकनीकी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों आदि के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए. लेकिन हमें इन्हीं उपलब्धियों के साथ संतुष्ट नहीं होना है. हमें यह संकल्प भी लेना है कि आगामी वर्षों में हम गंभीर आर्थिक विषमता और निर्धनता को पूरी तरह समाप्त करेंगे.

डीएम सोनिका ने हनोल देवता मंदिर के जागड़ा आयोजन की व्यवस्थाओं पर दिए निर्देश

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में हनोल देवता मंदिर त्यूणी में जागड़ा आयोजन की व्यवस्थाओं के संबंध में मंदिर समिति के सदस्यों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उप जिलाधिकारी त्यूणी को 20 अगस्त तक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए समुचित व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने हेतु मंदिर समिति के पदाधिकारियों से सुझाव भी प्राप्त किए। उन्होंने उप जिलाधिकारी चकराता/त्यूणी एवं जिला पर्यटन अधिकारी को जागड़ा के दौरान विभिन्न व्यवस्थाएं बनाने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी चकराता को जागड़ा आयोजन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर परिसर में पार्किंग व्यवस्था के साथ ही मंदिर के निकटवर्ती क्षेत्रों में वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोनिवि, पीएमजीएसवाई, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सड़कों के किनारे मलवा हटाने व झाड़ी साफ करने के निर्देश दिए तथा जहां पर मरम्मत कार्य किए जाने है वहां पर तत्काल कार्य करें। उन्होंने परिवहन विभाग को जागड़ा दिवस 30 एवं 31 अगस्त को विभिन्न रूटों पर परिवहन व्यवस्था बनाने तथा निर्धारित किराया से अधिक न वसूला जाए इस पर ध्यान देने, पुलिस विभाग को ओवरलोडिंग न हो इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। जल संस्थान को पेयजल व्यवस्था दुरूस्त करने, विद्युत विभाग को विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्थाएं बनाने, स्वास्थ्य विभाग को दवाईयां, एम्बुलेंस के साथ ही नजदीकि चिकित्सालय में व्यवस्थाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही वैकल्पिक हैलीपेड हेतु स्थान चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मंदिर परिसर में साफ-सफाई एवं पर्याप्त मात्रा में शौचालय आदि व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में उप जिलाधिकारी चकराता सौरभ असवाल, प्रभारी वनाधिकारी चकराता कल्याणी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कमलेश उपाध्याय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 मनोज कुमार उप्रेती, पुलिस उपाधीक्षक संदीप नेगी, भारतीय पुरातत्व विभाग से मनोज कुमार सक्सेना, सहायक निदेशक सूचना बद्री चन्द्र नेगी, जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल सिंह सहित लोनिवि, विद्युत, जल संस्थान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्मिकों सहित सचिव मंदिर समिति मोहन लाल सेमवाल, कोषाध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत, पुजारी राजेन्द्र नौटियाल प्रबंधक नरेन्द्र नौटियाल उपस्थित रहे।

भाईचारा को मजबूत करने की जरूरत : डॉ. फारूक

फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। देश की एकता व अखंड़ता के लिये हम सबको एक साथ मिल कर काम करने ओर जो आजादी मिली है, उसके लिये भाईचारा को मजबूत करने की जरूरत है। यह बात 'एक शाम देश के नाम' यौम-ए-आजदी कीपर आयोजित मुशायरा एवं कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए तस्मिया सोसाईटी के अध्यक्ष डॉ. एस फारूक ने कही। उन्होने कहा कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहें है, हमारी वाणी में भी अमृत बस जाए, संयम प्रदर्शित ऐसा व्यवहार करने की अवयकश्ता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि एशिया कार्विंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. सरफराज हसन ने जंग-ए-आजादी में दिये गये योगदान पर प्रकाश डाला। कहा कि आज का यह कार्यक्रम एकता, भाईचारे व अमन का संदेश देता है, हमारे पूर्वजों ने एक साथ मिल कर जिस प्रकार आजादी का संग्राम जीता वैसे ही आज देश के निमार्ण में हम सबकों मिलकर काम करना होगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर.केजी बहल, डॉ. एमएस अंसारी, जीएस जस्सल, फादर जेपी सिंह व भूपेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। मुशायरे का आगाज शमा रोशन व राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर गुलफाम अहमद ने तराना व जिकरिया गौहर, कय्यूम बिस्मिल, अंबिका सिंह रूही,रउफ अहमद, शौहर जलालाबादी, रईस फिगार, इनाम रम्जी, इम्तियाज अकबराबादी, नदीम बर्नी, तौसीर अहमद, अमजद खन अमजद, शादाब मशहदी व आरिफ शेरकोटी ने अपनी शायरी-कविता से उपस्थित श्रोत्रागणों को मंत्रमुगध कर दिया। एशिया कार्विंग्स, एएनपीएसआर व उत्तरांचल उर्दू अकादमी सोसाईटी की ओर से आयोजित मुशायरे में समाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जेबा नाज अंसारी, डॉ. रहमान, मास्टर आबिद हसन अंसारी, मास्टर अब्दुल सत्तार, आरिफ खान, बीएस जस्सल, अलिन वर्मा, अरूण कुमार अपने-सपने सोसाइटी, बीना शर्मा बुक बैंक, भरत शर्मा, दामिनी ममगई, डॉ रमन प्रीत, शेरिंग लुडिंग तारा फाउंडेशन, गजेंद्र रमोला न्यो विजन संस्था व विजय राज छोटी सी दुनिया को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुशायरे का संचालन मौहम्मद शाहनजर ने किया।

- म'एक शाम देश के नाम' मुशायरा-कवि सम्मेलन आयोजित
- म'एक शायरों-कवियों ने श्रोत्राओं को किया मंत्रमुग्ध

सीएम से मिले स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन के पिता

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देर सायं मुख्यमंत्री आवास में कॉमनवेल्थ गेम्स में बेडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन के पिता डी.के. सेन ने भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को फोन पर स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य ने अपनी खेल प्रतिभा से उत्तराखण्ड का ही नहीं देश का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने पिछली बार लक्ष्य से मुलाकात के दौरान उनसे लक्ष्य भेद कर आने को कहा था। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य से कहा कि उन्हें दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। आसमान छूना है, झुकना नही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कहते है हमारे खिलाड़ियों को अपना रिकार्ड खुद ही तोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य सेन की इस सफलता के पीछे उनके माता-पिता की तपस्या का भी प्रतिफल है।

निरंकुश ट्रैफिक पुलिस देहरादून की व्यवस्था पर बदनुमा दाग : राजीव महर्षि

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आजादी के अमृत महोत्सव पर स्मार्ट सिटी में शामिल देहरादून की यातायात व्यवस्था ने नागरिकों को बुरी तरह हताश, निराश और मायूस किया। यह जश्न में डूबे लोगों को हुई इस तरह की अनुभूति जैसा रहा, जैसे भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ परोसे गए भोजन में मानो जानबूझ कर कंकर डाल दिया गया हो। शहर तो स्मार्ट तो नहीं बन पाया किंतु यातायात पुलिस स्मार्ट जरूर हो गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिना पार्किंग वाले शहर में यातायात पुलिस की स्मार्टनेस के सिवा कुछ नहीं है। आपकी गाड़ी कब लॉक हो जाए, कहीं भी और कभी भी नो पार्किंग के बहाने आपकी गाड़ी उठा ली जाए, कोई भरोसा नहीं है। चाहे आप एक मिनट के लिए ही गाड़ी पार्क कर किसी दुकान, प्रतिष्ठान या सरकारी - गैर सरकारी दफ्तर ही क्यों न गए हों। आपको स्मार्ट सिटी में होने की कीमत कम से कम पांच सौ रुपए जुर्माने के साथ चुकानी पड़ सकती है। रोजाना दसियों लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। जरूरी नहीं कि कहीं नो पार्किंग का बोर्ड लगा हो और आपने अनजाने में गाड़ी वहां पार्क कर दी।

वैसे तो नो पार्किंग कुछ खास जगहों पर ही है और स्थानीय प्रशासन द्वारा पार्किंग की भी सीमित व्यवस्था ही की गई है, यातायात पुलिस को इस जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है और न ही लोगों की समस्या के प्रति संवेदनशीलता ही है। उसके हाथ में डंडा है और आम आदमी की पीठ। बस यही स्मार्ट सिटी का पैमाना है। सड़कों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। देहरादून की सड़कें देख कर तो कहीं से यह आभास नहीं होता कि यह स्मार्ट सिटी का पासंग भी हो किंतु ट्रैफिक पुलिस जरूर स्मार्ट है। कहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही स्मार्ट है।

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने दून की ट्रैफिक व्यवस्था पर गहरी नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में लेते हुए कहा है कि पहले तो स्पष्ट रूप से नो पार्किंग जोन घोषित किया जाना चाहिए। बाहर से आने वाले लोगों को देहरादून आने का दंड 500 रुपए जुर्माने के साथ न चुकाना पड़े, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, साथ ही स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि देहरादून में ट्रैफिक पुलिस इस कदर निरंकुश हो गई है कि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। किसी की भी गाड़ी, कभी भी, कहीं से भी उठाई जा सकती है। आपकी आंखों के सामने यह हो सकता है लेकिन आम लोगों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। घर से बाहर निकलना हो तो पांच सौ रुपए ट्रैफिक पुलिस के लिए लेकर चलना अनिवार्यता हो गया है।राजीव महर्षि ने कहा कि बिना प्रबंध किए ट्रैफिक पुलिस को जिस तरह निरंकुश बना दिया गया है, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। शहर की सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं, विस्तार की कहीं गुंजाइश नहीं है, ऐसे में चालानी कार्यवाही निसंदेह लोगों का शोषण है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।महर्षि नेकहा कि रोजाना उनके पास दर्जनों लोग ट्रैफिक पुलिस के अवांछित आचरण की शिकायतें लेकर लोग पहुंचते हैं। उन्होंने मांग की है कि शहर में पहले पार्किंग की ठोस व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही ट्रैफिक पुलिस को डंडा थमाया जाए।

उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री को इस अव्यवस्था का संज्ञान लेकर ट्रैफिक पुलिस के पेंच कसने होंगे, अन्यथा उनके सुशासन के नारे पर हमेशा सवालिया निशान लगा रहेगा। उन्होंने कहा कि निरंकुश ट्रैफिक पुलिस देहरादून के प्रशासन पर बदनुमा दाग है और सरकार को इस दिशा में सबसे पहले सोचने की जरूरत है। केवल नारों से काम नहीं चलेगा। जमीन पर काम करना होगा और उसके लिए शहर में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद ही ट्रैफिक पुलिस को लोगों पर हाथ डालने की अनुमति दी जाए।

हल्द्वानी से NASA तक, चंद्रमा पर इंसानों को ठहराने वाली न्यू मून प्रोग्राम आर्टेमिस का हिस्सा बने अमित पांडे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

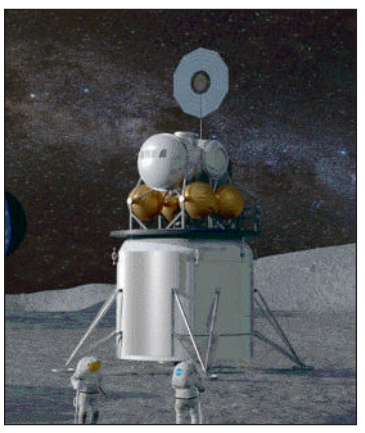

उत्तराखंड के लिए ये बड़ी ख़ुशी की बात है की हल्द्वानी निवासी अमित पांडे का चयन वरिष्ठ विज्ञानी के पद पर NASA में हुआ। वह चंद्रमा पर इंसानों को ठहराने वाली न्यू मून प्रोग्राम आर्टेमिस का हिस्सा होंगे। अमित पांडे उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी के रहने वाले है. अमित पांडे चंद्रमा पर इंसानों को ठहराने वाली न्यू मून प्रोग्राम आर्टेमिस का हिस्सा (NASA Artemis Moon Missions) होंगे. अमित पांडे की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है तो वहीं अमित की इस उपलब्धि से उत्तराखंड का भी नाम रोशन हुआ है।

फिलहाल नासा के इस मिशन की योजना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार नासा का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक दल के साथ एक चौकी स्थापित करना है, जिसे चंद्रमा पर हमारा पहला पैर पकड़ कहा जा रहा है. इस प्रोजेक्ट पर अमित पांडे काम कर रहे हैं। बता दे अमित पांडे की प्रारंभिक शिक्षा हल्द्वानी के केंद्रीय विद्यालय से हुई है, जबकि 12वीं की परीक्षा रायबरेली के केंद्रीय विद्यालय से की. अमित पांडे का घर गोरापड़ाव में है. पिता विपिन चंद्र पांडे महात्मा गांधी इंटर कालेज से सेवानिवृत शिक्षक हैं. मां सुशीला पांडे गृहिणी हैं. अमित ने कक्षा 10 तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय और 12वीं की परीक्षा रायबरेली के केंद्रीय विद्यालय से की। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक करने के बाद वर्ष 2003 में अमेरिका चले गए। 2005 में यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना से मास्टर डिग्री, 2009 में यूनिवर्सिटी आफ मेरीलैंड से पीएचडी हासिल पूरी की। तब से वह अमेरिका की कई प्रसिद्ध कपंनियों में कार्य कर चुके हैं अमित पांडे के अनुसंधान को लेकर उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है. अब उनका चयन सीनियर साइंटिस्ट के पद पर NASA में हुआ है. वह चंद्रमा पर इंसानों को ठहराने वाली न्यू मून प्रोग्राम आर्टेमिस (NASA Artemis Moon Missions) का हिस्सा होंगे. अमित अपने यूट्यूब चैनल के जरिये करियर काउंसलिंग भी करते हैं और हर तरह की मदद को भी तैयार रहते हैं. वह खुद भी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं.

उत्तराखंड में फिर बरसने वाले हैं बादल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड में फिर से काले बादल आ रहे हैं, जो इस बार जमकर बरसेंगे, मौसम विभाग के मुताबिक 17 और 18 अगस्त को बहुत हल्की बारिश होगी। और उसके अगले दो दिनों तक रहेगा सूखापन, जिसमे कहीं भी भारी बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि, 19 और 20 अगस्त को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना है। जिससे राज्य में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मंगलवार को देहरादून में सुबह से ही धूप खिली हुई थी। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है।

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के मुताबिक 18 और 19 अगस्त को दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे दोनों दिन ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।वहीं, उत्तराखंड में सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश हुई है। कम वर्षा के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम आधारित खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा